भारत में सर्पदंश से मृत्यु

चर्चा में क्यों ?

- ✓ हाल ही में, केरल वन विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सर्पदंश से सबसे अधिक मानव मृत्यु होती है, जो जंगली हाथियों की तुलना में लगभग दोगुनी है।

प्रमुख बिंदु

- ✓ ICMR अध्ययन के अनुसार, भारत में 2000 से 2019 तक अनुमानित 1.2 मिलियन (12 लाख) लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हुई है। वैश्विक स्तर पर सर्पदंश से होने वाली मौतों में से लगभग 50% भारत में होती हैं।
- ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा साँप के काटने से फैले जहर को उच्च प्राथमिकता वाली उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- ✓ सर्पदंश का जहर एक जहरीले सांप के काटने में विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली संभावित जान लेवा बीमारी है।
- ✓ सांपों की कुछ प्रजातियों द्वारा आंखों में जहर छिड़कने से भी ज़हर फ़ैल सकता है।
- ✓ सांप के जहर में कई एंजाइम या प्रोटीनयुक्त पदार्थ होते हैं, जो सांप की प्रजाति के अनुसार अलग-अलग मात्रा में मौजूद होते हैं, जो रक्त, तंत्रिका तंत्र या अन्य ऊतकों पर हमला करते हैं।

प्रभाव

- ✓ कुछ विष सीधे विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनमें से सभी मनुष्य के लिए घातक नहीं होते हैं। कुछ अत्यंत रूप से घातक होते हैं (जैसे- रैटलस्नेक का जहर), जबकि कुछ मुख्य रूप से काटने के आस-पास के ऊतकों के लिए विनाशकारी होते हैं, लेकिन गैंग्रीन के विकास का कारण बन सकते हैं।
- ✓ भारत में पीड़ितों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में सर्पदंश पर उपेक्षा और ध्यान की कमी प्रदर्शित होती है।
- ✓ इसे एक गरीब व्यक्ति की बीमारी या ग्रामीण समस्या माना जाता है। सांपों द्वारा काटे जाने वाले लोग आमतौर पर हाशिए के समुदायों, ग्रामीण पृष्ठभूमि, महिलाओं और बच्चों में होते हैं।

- ✓ **चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण चार बड़े सांप:** यह एक सिद्धांत है जो दावा करता है कि दक्षिण एशिया में सांपों की चार प्रजातियां, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, चश्माधारी कोबरा और सामान्य क्रेट इस क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा काटते हैं।
- ✓ भारत में, लगभग 90% सर्पदंश 'बिग फोर' के कारण होते हैं।

सांप के काटने का इलाज

- ✓ सर्पदंश विष के अधिकांश हानिकारक प्रभावों को रोकने या उलटने के लिए सर्प विषरोधक प्रभावी उपचार है जो WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है।
- ✓ **एंटीवेनम:** एंटीवेनम विष या विष घटकों के खिलाफ शुद्ध एंटीबॉडी होते हैं। एंटीवेनम जानवरों द्वारा इंजेक्ट किए गए जहरों के लिए बनाए गए एंटीबॉडी से निर्मित होते हैं। जहरीले सांपों द्वारा काटने पर एंटीवेनम एकमात्र प्रभावी उपचार है।
- ✓ वैज्ञानिक, जानवरों को जहर की एक छोटी एवं हानिरहित खुराक के साथ इंजेक्ट करते हैं, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी प्रोटीन का उत्पादन करती है जो जहर के विषाक्त पदार्थों पर हमला करती है और उन्हें निष्क्रिय कर देती है।

चुनौतियां

- ✓ जागरूकता की कमी, सर्पदंश की रोकथाम के बारे में अपर्याप्त ज्ञान और समुदाय के बीच प्राथमिक उपचार की कमी के कारण चिकित्सा देखभाल अक्षम हो जाती है।
- ✓ परिधीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, जीवन रक्षक उपचार प्राप्त करने में देरी और सर्पदंश के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की अनुपलब्धता अधिक संख्या में मौतों में योगदान करते हैं।
- ✓ सांप के काटने के बारे में अंधविश्वास: जहरीले सांप और सांप के काटने की पहचान को लेकर समुदाय की गलत धारणा । नाग देवता में विश्वास, विष के प्रभाव को कम करने के लिए इमली के बीजों या चुम्बकों का प्रयोग।
- ✓ किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जहरीले और गैर-विषैले सांपों की पहचान, रोकथाम, प्राथमिक चिकित्सा और सर्पदंश के उपचार पर कोई सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- ✓ भारत में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में सर्पदंश प्रबंधन को शामिल करना, चिकित्सा स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान अनिवार्य अल्पकालिक प्रशिक्षण और भारत में राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने पर प्रेरण प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में भी शामिल करना।
- ✓ सर्पदंश की रोकथाम को केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाना।
- ✓ सामुदायिक जागरूकता का एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, भारत में सर्पदंश के जहर के कारण मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता निर्माण।

- ✓ प्रत्येक गाँव-स्तर के स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) होता है, जो उपचार का पहला चरण है, जो पहले ग्रामीण भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं था।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

- ✓ राजस्थान विधानसभा में एक वरिष्ठ विधायक और विपक्ष के उप नेता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर हंगामा किया गया।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

- ✓ संसद के सभी सदस्य (सांसद) व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अधिकारों और प्रतिरक्षा का अधिकार रखते हैं, ताकि वे अपने कर्त्तव्यों और कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
- ✓ जब लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य द्वारा इन अधिकारों और उन्मुक्तियों की अवहेलना की जाती है, तो यह एक अपराध है, जिसे 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' कहा जाता है, जो संसद के कानूनों के तहत दंडनीय है।
- ✓ किसी भी सदन का कोई भी सदस्य प्रस्ताव के रूप में उस सदस्य के खिलाफ नोटिस दे सकता है, जिसे वह विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी मानता/मानती है।
- ✓ संसद के दोनों सदनों के पास कानूनों के अनुसार अवमानना के किसी भी कार्य (आवश्यक रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं) को दंडित करने का अधिकार सुरक्षित है।

विशेषाधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम

- ✓ कोई सदस्य, अध्यक्ष या सभापति की सहमति से, किसी सदस्य या सदन या उसकी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है।
- ✓ नियमों के अनुसार कोई भी नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और इसमें सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।

अध्यक्ष/सभापति की भूमिका

- ✓ अध्यक्ष/सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जाँच का पहला स्तर होता है।अध्यक्ष/सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं।

IMF और बांग्लादेश

चर्चा में क्यों ?

- ✓ IMF के द्वारा बांग्लादेश के लिए $4.7 बिलियन सहायता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गयी।

210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Contact Us 9999516388, 8595638669

प्रमुख बिंदु

- ✓ **बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था**: फंडिंग में IMF की विस्तारित क्रेडिट सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रमों के तहत 3.3 बिलियन डॉलर और नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा (RSF) के तहत 1.4 बिलियन डॉलर शामिल हैं।
- ✓ IMF के कार्यकारी बोर्ड ने मौजूदा विनिमय दरों पर बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर के समर्थन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिससे दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश अपनी नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा (RSF) तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है।
- ✓ फंडिंग में IMF की विस्तारित क्रेडिट सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रमों के तहत $3.3 बिलियन और नए RSF के तहत $1.4 बिलियन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कमजोर मध्य-आय वाले देशों और द्वीपीय देशों की मदद करना है।
- ✓ IMF ने कहा कि 42 महीने का उधार पैकेज "व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा, कमजोर लोगों की रक्षा करेगा और समावेशी और हरित विकास को बढ़ावा देगा।"
- ✓ इसमें से अधिक सामाजिक और विकासात्मक खर्च को सक्षम करने, बांग्लादेश के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, राजकोषीय और शासन सुधारों को बढ़ावा देने और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए राजकोषीय स्थान बनाने पर केंद्रित सुधार शामिल हैं।

दलित धर्मांतरितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जाँच

चर्चा में क्यों ?

- ✓ हालिया बजट में दलित धर्मांतरितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जाँच करने के लिए पैनल ने 3.05 करोड़ रू. आवंटित किए।

प्रमुख बिंदु

- ✓ सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दलित ईसाईयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जाँच के लिए तीन सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है।
- ✓ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, वर्तमान में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- ✓ सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार, आयोग दलित ईसाईयों और मुसलमानों के साथ उनके नए धार्मिक दायरे में होने वाले भेदभाव की "दमनकारी गंभीरता" को स्थापित करेगा।
- ✓ धर्मान्तरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

- ✓ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 2011 और 2012 में शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा गया था कि वे उन दलितों के अनुसूचित जाति के दर्जे का विस्तार करने के पक्ष में थे, जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना

चर्चा में क्यों ?

- ✓ हाल ही में केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' की घोषणा की गयी है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के बारे में:

- ✓ इस योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान की गयी है।
- ✓ यह 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है जो दर पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स अकाउंट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) की तुलना में बहुत अधिक है।
- ✓ NSC पर 7%, PPF स्कीम पर 7.1 % और किसान विकास पत्र पर 7.2 % ब्याज मिलता है।
- ✓ यह दो साल की अवधि हेतु 2025 तक उपलब्ध है।
- ✓ **लाभ:** यह और अधिक महिलाओं को औपचारिक वित्तीय बचत साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

THE STUDY
KARMANYE VADHIKARASTE MA PHALESHU KADACHAN
An Institute for IAS